35. स्थानीय प्रशासन

❑ पंचायती राज व्यवस्था है- [ग्राम सेवक परीक्षा, 18.12.2016]
[पटवारी प्रारम्भिक परीक्षा-2016]
(1) ग्रामीण स्थानीय स्व-शासन (2) स्थानीय स्वशासन
(3) स्थानीय सरकार (4) स्थानीय प्रशासन की
Ans. (1)

व्याख्या – ग्रामीण स्थानीय स्व-शासन अथवा पंचायती राज – भारत में 'स्थानीय स्वशासन' को राज्य सूची के अन्तर्गत रखा गया है। गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम 1882 में जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत का प्रस्ताव कर देश में स्थानीय स्वशासन की ठोस बुनियाद रखी। इस कारण रिपन को देश में 'स्थानीय स्वशासन का पिता' कहा जाता है।

❑ निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौनसा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73 वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? [ग्राम सेवक18.12.16][संरक्षण अधिकारी-29.5.19]
(1) 243 से 243 -O (2) 243 से 243-T
(3) 243 से 243-ZA (4) 244 से 244-P
Ans. (1)

व्याख्या : 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 O तक को 9वें भाग के रूप में जोड़कर 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को सांविधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।

❑ भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौनसा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? [PSI (मोटर वाहन) - 12.02.2022]
(1) 75वाँ (2) 73वाँ (3) 71वाँ (4) 72वाँ
Ans. (2) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❑ किस अनुच्छेद के तहत् पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया- [पटवार-23.10.2021 (Shift -I]
(1) 221 (2) 227 (3) 243 (4) 241
Ans. (3) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❑ भारतीय संविधान की कौनसी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है?[द्वितीय श्रेणी शिक्षक -2014]
(1) तीसरी (2) चौथी (3) दसवीं (4) ग्यारहवीं
Ans. (4) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❑ निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 से हैं-
[राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-08.11.2020 (II)]
(1) पंचायती राज (2) नगर पालिकाएँ
(3) दलबदल विरोधी कानून (4) मौलिक कर्तव्य
Ans. (1) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❑ संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार कौनसे कथन सही है? [VDO Mains -09.07.2022]
1. पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम 2/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
2. 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया।
3. मध्यप्रदेश 73वां सांविधानिक संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था।
4. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल, 1994 से लागू हुआ।
(1) 1, 3 (2) 2, 3
(3) 2, 3 और 1 (4) 2, 3 और 4
Ans. (*)

व्याख्या : विकल्प 3 गलत है अतः बोनस अंक दिया। 16 सितम्बर, 1991 को पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार द्वारा पंचायती राज के संबंध में 73वाँ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक की समीक्षा हेतु नाथुराम मिर्धा की अध्यक्षता में लोकसभा की इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 22 दिसम्बर, 1992 को लोकसभा द्वारा तथा 23 दिसम्बर, 1992 को राज्यसभा में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 पारित किया गया। 17 राज्यों के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने इसे 20 अप्रैल, 1993 को अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा एक अधिसूचना द्वारा 24 अप्रैल, 1993 को यह अधिनियम देश में लागू हो गया। इसलिए 24 अप्रैल को 'पंचायती राज दिवस' मनाया जाता है।

❑ निम्न में से कौन सा कथन पंचायती राज्य संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है? [CET -11.2.2023 (S-II)]
(1) सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत हुई।
(2) 73वाँ संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ।
(3) ग्यारहवीं अनुसूची में कुल 29 विषय है।
(4) ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है।
Ans. (*)

Scanned with OKEN Scanner

> **व्याख्या :** *विकल्प 2 और 4 गलत है। ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। 73वाँ संविधान संशोधन विधेयक 1993 में लागू हुआ।*

❑ **भारतीय संविधान के कौनसे अनुच्छेद में 'ग्राम सभा' की परिभाषा है-** [PTI (Grade II)-30.4.2023] [VDO-27.12.2021 (S-I)]

(1) अनुच्छेद -243 ग (2) अनुच्छेद -243
(3) अनुच्छेद - 243 क (4) अनुच्छेद - 243 ख

Ans. (2)

> **व्याख्या** – *पंचायतें (भाग 9) : संवैधानिक प्रावधान*

अनुच्छेद 243	–	*परिभाषाएँ*
अनुच्छेद 243 A	–	*ग्राम-सभा*
अनुच्छेद 243 B	–	*पंचायतों का गठन*
अनुच्छेद 243 C	–	*पंचायतों की संरचना*
अनुच्छेद 243 D	–	*स्थानों का आरक्षण*
अनुच्छेद 243 E	–	*पंचायतों की अवधि आदि*
अनुच्छेद 243 F	–	*सदस्यता के लिए निरर्हताएँ*
अनुच्छेद 243 G	–	*पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व*
अनुच्छेद 243 H	–	*पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियों और उनकी निधियाँ*
अनुच्छेद 243 I	–	*वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन*
अनुच्छेद 243 J	–	*पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा*
अनुच्छेद 243 K	–	*पंचायतों के लिए निर्वाचन*
अनुच्छेद 243 L	–	*संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना*
अनुच्छेद 243 M	–	*इन भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू होना*
अनुच्छेद 243 N	–	*विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना*
अनुच्छेद 243 O	–	*निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन*

❑ **भारतीय संविधान का कौनसा अनुच्छेद ग्रामसभा के बारे में है?** [III Grade (SST) -26.02.2023]

(1) 243 D (2) 243 A (3) 243 F (4) 243 C

Ans. (2) **व्याख्या :** *उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❑ **पंचायत राज के संबंध में कौनसा (प्रावधान -अनुच्छेद) युग्म गलत है-** [VDO-28.12.2021 (S-I)]

(1) वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन–243 झ
(2) पंचायतों के लिए निर्वाचन–243 क
(3) पचायतों की अवधि–243ङ
(4) स्थानों का आरक्षण–243 घ

Ans. (2) **व्याख्या :** *उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❑ **संविधान का कौनसा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के एक-तिहाई प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है?** [II Grade GK - 22.12.2022]

(1) अनुच्छेद 243-D (2) अनुच्छेद 243-I
(3) अनुच्छेद 243-H (4) अनुच्छेद 243-C

Ans. (1) **व्याख्या :** *उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❑ **निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई?** [CET -11.2.2023 (S-I)] [राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल-06.11.2020 (II)] [II Grade (Sanskrit Dept.) -12.2.2023(S-I)]

(1) 1954 (2) 1952 (3) 1973 (4) 1953

Ans. (1)

> **व्याख्या** – *आधुनिक राजस्थान के गठन से पूर्व भी राजस्थान की विभिन्न देशी रियासतों यथा-जोधपुर, बीकानेर (1928), जयपुर (1938), सिरोही (1943), भरतपुर (1944), उदयपुर और करौली (1949) में पंचायती राज कानून बनाये गये। राजस्थान में बीकानेर पहली देशी रियासत थी जहाँ 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में उल्लिखित दर्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। 1953 में विधानसभा द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1953 पारित किया गया जिसे 1 जनवरी, 1954 में अधिनियम का स्वरूप दे दिया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई।*

❑ **राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चुनाव करें-**

1. जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए।
2. बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था।
3. 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। [II Grade (Sanskrit Dept.) -12.2.2023(S-II)]

(1) 1, 2 और 3 सही है। (2) 1 और 2 सही हैं।
(3) 2 और 3 सही हैं। (4) 1 और 3 सही हैं।

Ans. (2) **व्याख्या :** *उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

Scanned with OKEN Scanner

कथन सही नहीं है- [Asst. Professor- 7.1.2024]
(1) बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था।
(2) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितम्बर-अक्टूबर, 1959 में आयोजित हुए।
(3) पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर, राजस्थान में किया गया।
(4) 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई।
Ans. (4) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❑ **राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि है-** [Stenographer-30.5.13] [II Grade (Hindi) 2011] [RPSC II Grade Teacher Exam-2011]
(1) 26 जनवरी, 1957 (2) 24 अप्रैल, 1993
(3) 2 अक्टूबर, 1959 (4) 15 अगस्त, 1958
Ans. (3)

व्याख्या -भारतवर्ष में सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायतीराज व्यवस्था का शुभारम्भ जवाहर लाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 नागौर के बगदरी गाँव से किया गया।

❑ **राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी ?** [EO & RO : 14.05.2023 (S-I)]
(1) बलिया (2) नागौर (3) चंबल (4) नागपुर
Ans. (2) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❑ **राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किया गया था?** [CET : 04.02.2023 (I)][पुलिस कॉन्स्टेबल-08.11.2020 (II)]
(1) तृतीय (2) चतुर्थ (3) प्रथम (4) द्वितीय
Ans. (4) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❑ **राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया ?** [पटवार - 2011] [EO & RO 14.5.2023 (II)][II Gr.(संस्कृत शिक्षा) -19.2.2019]
(1) 2 अक्टूबर 1959, पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा।
(2) 15 अगस्त 1957, पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा।
(3) 26 जनवरी 1952, महात्मा गांधी द्वारा।
(4) 2 अक्टूबर 1959, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा।
Ans. (1) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❑ **किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज लागू किया गया?** [R.A.S. Pre, 1995] [Police Constable -2007(I)] [II Grade (Urdu)2011][पटवार परीक्षा - 2008]
(1) गुजरात (2) राजस्थान (3) बिहार (4) आंध्रप्रदेश
Ans. (2) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❑ **राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है-** [Head Master-15 May, 2012][पटवार - 2011]
(1) ग्राम सभा (2) जिला आयोजना समिति
(3) पंचायत समिति (4) जिला परिषद्
Ans. (3)

व्याख्या - त्रिस्तरीय -निम्नतम स्तर - ग्राम पंचायत, मध्य स्तर - पंचायत समिति, शीर्ष स्तर - जिला परिषद्

❑ **निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्व-निकाय की संस्था नहीं है-** [छात्रावास अधीक्षक -28.07.2024]
(1) ग्राम पंचायत (2) जिला परिषद
(3) पंचायत समिति (4) नगरपालिका
Ans. (4) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❑ **पंचायतों की अवधि है?** [पटवार परीक्षा - 2008]
(1) 5 वर्ष (2) 4 वर्ष (3) 3 वर्ष (4) 2 वर्ष
Ans. (1)

व्याख्या - प्रत्येक पंचायतीराज संस्था का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक का होगा।

❑ **राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे सम्बोधित करते हैं?** [II Grade (Sans. Deptt.) -17.02.2019] [VDO-28.12.2021 (I)] [जेल प्रहरी- 2017][वनरक्षक-13.12.2022(I)]
(1) जिला प्रमुख (2) विकास अधिकारी
(3) पंचायत समिति का प्रधान (4) जिला कलेक्टर
Ans. (2)

व्याख्या-पंचायत राज व्यवस्था में सदस्यों का त्यागपत्र-
- *ग्राम स्तर - विकास अधिकारी को*
- *पंचायत समिति स्तर - प्रधान को*
- *जिला स्तर - जिला प्रमुख को*

❑ **राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है?** [Police Constable Exam- 2013]
(1) जिला प्रमुख (2) उप-प्रधान
(3) जिला कलक्टर (4) संभागीय आयुक्त
Ans. (1)

Scanned with OKEN Scanner

> **व्याख्या-पंचायत राज व्यवस्था में अध्यक्षों का त्यागपत्र-**
> - ग्राम स्तर (सरपंच) - विकास अधिकारी को
> - पंचायत समिति स्तर (प्रधान) - जिला प्रमुख को
> - जिला स्तर (जिला प्रमुख)-संभागीय आयुक्त को

❒ राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं-[VDO-27.12.2021 (S-II)][RAS-28.8.2016]

(1) 35 (2) 30 (3) 40 (4) 25

Ans. (4)

> **व्याख्या : जिला आयोजना समितियाँ :** अनु. 243ZD के अधीन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 में जिला आयोजना समिति के गठन का प्रावधान है। ये जिले की 'विकास योजना' का निर्माण करने हेतु जिला प्रमुख की अध्यक्षता में गठित समितियाँ है। इसका सचिव मुख्य आयोजना अधिकारी होता है। इनमें कुल 25 सदस्य होते हैं जिनमें से 3 पदेन व 2 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं तथा 20 सदस्य जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में जिला परिषद/नगर निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों में निर्वाचित होते हैं। पदेन सदस्य - (अ) जिले का कलक्टर, (ब) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (स) अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्

❒ राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? [JEN (Mechanical) Diploma- 20.05.2022]

(1) जिला कलेक्टर (2) जिला प्रमुख

(3) वित्त मंत्री (4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Ans. (2) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❒ **संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं?**

[II Grade - 30.07.2023 (S- II)][Head Master - 15 May, 2012] [PTI - 23.02.2015, 30.09.2018][II Grade GK - 22.12.2022]

(1) 29 (2) 30 (3) 35 (4) 37.

Ans. (1)

> *व्याख्या - संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए 29 विषय सूचीबद्ध है। जिनमें 21 (16 + 5 नये) विषय पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिये गये है।*

❒ निम्नलिखित में से कौनसा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? [मूल्यांकन अधिकारी-2020]

(1) पशुपालन (2) लघु उद्योग

(3) काँजी हाउस (4) बाजार एवं मेले

Ans. (3)

> ***व्याख्या-पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली 29 शक्तियाँ दी गई है-*** *1. कृषि, 2. भूमि सुधार व मृदा संरक्षण, 3. लघु सिंचाई, जलप्रबंध और जलग्रहण विकास, 4. पशुपालन, डेयरी व मुर्गीपालन, 5. मत्स्य पालन, 6. सामाजिक वानिकी व कृषि वानिकी, 7. लघु वनोपज, 8. लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समेत, 9. खादी व ग्रामीण कुटीर उद्योग, 10. ग्रामीण आवास, 11. पेयजल, 12. ईंधन व चारा, 13. सड़कें, नालियाँ, पुल, जलमार्ग व अन्य साधन, 14. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 15. सामुदायिक संपदा का रखरखाव, 16. शिक्षा, प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों समेत, 17. तकनीकी प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा, 18. प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा, 19. पुस्तकालय, 20. सांस्कृतिक गतिविधियाँ, 21. हाट व मेले, 22. स्वास्थ्य व साफ-सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व डिस्पेंसरियाँ समेत, 23. परिवार कल्याण, 24. महिला व बाल विकास, 25. समाज कल्याण, विकलांगों व विमंदित के कल्याण समेत, 26. कमजोर वर्गों का कल्याण खासकर अनुसूचित जाति व जनजाति, 27. ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत वितरण समेत, 28. गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत, 29. गरीबी उन्मूलन*

❒ निम्नलिखित में से कौनसा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है?

[II Grade (Sanskart Edu.) SST- 13.02.2023]

(1) महिला एवं बाल विकास (2) परिवार कल्याण

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (4) अग्निशमन सेवाएँ

Ans. (4) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❒ **पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है-** [II Grade (Urdu) Exam. 2011]

[जेल प्रहरी परीक्षा 20-10-2018, Shift -I]

(1) भारत निर्वाचन आयोग का

(2) पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार का

(3) राज्य निर्वाचन आयोग का

(4) मुख्य चुनाव अधिकारी, राजस्थान का

Ans. (3)

> *व्याख्या-पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने हेतु राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है।*

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का सम्बन्ध रहा है? [RPSC III Grade Teacher Exam-2006]
(1) पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से
(2) सहकारी समिति व्यवस्था के अध्ययन से
(3) मुस्लिम समुदाय की समस्या के अध्ययन से
(4) उच्च शिक्षा की स्थिति के अध्ययन से
Ans. (1)

व्याख्या – **पंचायती राज से सम्बन्धित समितियाँ :**

☞ **बलवन्त राय मेहता समिति**- सामुदायिक विकास परियोजनाओं एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं पर गठित इस समिति ने 24 नवम्बर, 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की।

☞ **सादिक अली अध्ययन दल**-1964 में गठित इस दल के अनुसार पंचायत समिति के प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव इन संस्थाओं के सदस्यों द्वारा किये जाने के स्थान पर वृहत्तर निर्वाचन मण्डल द्वारा किया जाना चाहिए।

☞ **गिरधारी लाल व्यास कमेटी**-1973 में गठित इस समिति ने प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम सेवक तथा सचिव नियुक्त करने तथा पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन बढ़ाये जाने पर बल दिया।

☞ **अशोक मेहता समिति**-दिसम्बर, 1977 में गठित इस समिति ने अगस्त, 1978 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को केवल जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर 'द्विस्तरीय पद्धति' में बदलना चाहिए।

☞ **जी. वी. के. राव समिति**-'ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए' योजना आयोग द्वारा 1985 में जी.वी.के. राव की अध्यक्षता में समिति गठन किया।

☞ **डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी**-1986 में राजीव गाँधी सरकार ने 'लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार' पर एक समिति का गठन एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में किया।

☞ **पी. के. थुंगन कमेटी**-1989 में संवैधानिकता पर विचार हेतु गठित समिति।

☞ **हरलाल सिंह खर्रा कमेटी**-1990 में गठित

☞ **दिलीप सिंह भूरिया समिति**-1994 में गठित यह समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है।

❒ **1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की?** [REET (L-II) -23.07.2022]
(1) पी.के. थुंगन समिति (2) बी. आर. मेहता समिति
(3) अशोक मेहता समिति (4) सादिक अली समिति
Ans. (1) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❒ **पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी?** [CET : 04.02.2023 (S-II)]
(1) अशोक मेहता समिति (2) जी.वी.के.राव समिति
(3) सादिक अली समिति (4) के.संस्थानम समिति
Ans. (1) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❒ **बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है-**
[VDO-28.12.2021 (S-II)] [ग्राम सेवक, 18.12.2016]
(1) राज्य प्रशासन (2) राजस्व सुधार
(3) केन्द्र राज्य संबंध (4) स्थानीय स्वशासन
Ans. (4) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❒ **ग्रामसभा का गठन होता है**-[RAS Pre -26.10.2013]
[Police Constable Exam-2006-07]
(1) पंच, उपसरपंच मिलकर
(2) ग्राम-पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही समस्त जनता से
(3) ग्राम-पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से
(4) पंचायत समिति क्षेत्र में पंजीकृत सभी मतदाताओं से
Ans. (3)

व्याख्या – राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 2 में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्रामसभा होगी, जिसके सदस्य उस पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति होंगे।

❒ **राजस्थान पंचायत राज्य अधिनियम 1994 के अध्याय - 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है, वह है-**
[REET L-II, 26.09.2021]
(1) ग्राम पंचायत (2) पंचायत समिति
(3) जिला परिषद् (4) ग्राम सभा
Ans. (4) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❒ **ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को ... कहा जाता है-** [छात्रावास अधीक्षक -28.07.2024]
(1) ग्राम पंचायत (2) पंचायत समिति
(3) जिला परिषद (4) ग्राम सभा
Ans. (4)

Scanned with OKEN Scanner

❐ ग्राम सभा की 'गणपूर्ति' कितनी है?

[छात्रावास अधीक्षक -28.07.2024]
[II Grade (Sans. Deptt.) -17.02.2019]

(1) कुल सदस्य संख्या का आधा भाग
(2) कुल सदस्य संख्या का चौथाई भाग
(3) कुल सदस्य संख्या का दसवाँ भाग
(4) कुल सदस्य संख्या का पाँचवाँ भाग

Ans. (3)

व्याख्या *- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा (8ए-8एफ) **गणपूर्ति :** कुल सदस्य संख्या के 10 प्रतिशत के बराबर होगी। **कार्य :** ग्राम विकास की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन।*

❐ राजस्थान में कौनसा नियम ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? [RAS-5.8.2018]

(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994
(2) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996
(3) राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999
(4) राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011

Ans. (4)

व्याख्या *- राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011 में राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जायेगी। संयुक्त बैठक में, प्रत्येक ग्राम सभा से सदस्यों के न्यूनतम 5 प्रतिशत या 10 सदस्यों, इनमें से जो भी कम हो, की उपस्थिति अनिवार्य होगी।*

❐ सरपंच और उप-सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा?

[II Grade GK (संस्कृत शिक्षा) -19.02.2019]
[उद्योग निरीक्षक परीक्षा-24.06.2018]

(1) खंड विकास अधिकारी (2) ग्राम सेवक
(3) ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति
(4) कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो।

Ans. (4)

व्याख्या *- प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की **कम से कम 2 बैठक** होगी, पहली वित्तीय वर्ष के त्रैमास में और दूसरी अंतिम त्रैमास में। लेकिन 2003 में इस स्थिति में परिवर्तन किया गया कि ग्राम सभा की चार बैठकें (26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त व 2 अक्टूबर को) आयोजित होंगी। इन बैठकों की अध्यक्षता सरपंच द्वारा, उसकी अनुपस्थिति में उपसरपंच द्वारा तथा दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित सदस्य द्वारा की जाएगी।*

❐ ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है? [CET : 04.02.2023 (S-II)]

(1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 2

Ans. (4)* ***व्याख्या :*** *उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❐ अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम-1996 का सम्बन्ध है-[राज.पुलिस कॉन्स्टेबल-13.6.2024 (I)][VDO-27.12.2021 (I)]

(1) शिक्षा (2) पंचायत राज सशक्तिकरण
(3) सांस्कृतिक विकास (4) आरक्षण क्षेत्र में विस्तार

Ans. (2)

व्याख्या *- **पेसा (Panchayat - Extension to Scheduled Areas) Act, 1996) :** पेसा (पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 24 दिसम्बर, 1996 में 10 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों में लागू किया गया। ये राज्य हैं- आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, ओडिशा व राजस्थान। यह अधिनियम भूरिया समिति द्वारा वर्ष 1995 में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लागू किया। राज्यों में पेसा प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु पंचायतीराज मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है। राजस्थान सरकार ने भी जून, 1998 में एक अध्यादेश जारी किया जिसके माध्यम से राजस्थान के अनुसूचित, जनजाति क्षेत्रों में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी बनाये गये हैं। इसके अनुसार इन क्षेत्रों की ग्रामसभाओं को व्यापक अधिकार दिये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना पीसारूल्स दिनांक 01.01.2011 के द्वारा "राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) नियम, 2011* लागू कर दिये गये हैं। इन नियमों को लागू करने पर पंचायती राज संस्थाओं को निम्नानुसार शक्तियां व अधिकार प्राप्त हो गये हैं - ☞ ग्राम सभा के परामर्श के पश्चात् ही भूमि अधिग्रहण का कार्य सरकार द्वारा किया जावेगा ☞ नशा नियंत्रण भी ग्राम सभा के पास रहेगा। ☞ उधार देने पर पंचायत का नियन्त्रण रहेगा। ☞ अतिचारियों की संक्षिप्त बेदखली की शक्तियाँ पंचायत समिति द्वारा उपयोग में ली जावेगी।*

Scanned with OKEN Scanner

❑ कौनसा कथन असत्य है? [CET : 08.01.2023 (S-I)]
(1) पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार (पेसा, PESA) अधिनियम 24 दिसम्बर, 1996 को लागू हुआ।
(2) पेसा (PESA) अधिनियम, दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया।
(3) पेसा (PESA) अधिनियम, अनुसूची-5 के 9 राज्यों में लागू है।
(4) इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परम्पराओं एवं रीति-रिवाज़ों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है।
Ans. (3) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❑ **राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011 के अन्तर्गत निम्नांकित में से कौनसी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलायी जा सकती है-** [PSI - 14.09.2021]
(1) ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम से कम 5 प्रतिशत या 25 सदस्यों, इसमें से जो भी अधिक हो, द्वारा सचिव को दी गयी लिखित सूचना के आधार पर।
(2) ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम से कम 10 प्रतिशत या 25 सदस्यों, इसमें से जो भी अधिक हो, द्वारा सचिव को दी गयी लिखित सूचना के आधार पर।
(3) ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम से कम 5 प्रतिशत या 50 सदस्यों, इसमें से जो भी अधिक हो, द्वारा सचिव को दी गयी लिखित सूचना के आधार पर।
(4) ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम से कम 10 प्रतिशत या 50 सदस्यों, इसमें से जो भी अधिक हो, द्वारा संचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर
Ans. (1)

व्याख्या -राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) नियम, 2011 की धारा 9(3) के अनुसार ग्राम सभा की विशेष बैठकें ग्राम सभा के कुल सदस्यों का कम से कम 5% या 25 सदस्यों, इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर बुलाई जायेगी। धारा 10 की उपधारा 4 के अनुसार ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठकों में प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों की न्यूनतम 5% या 10 सदस्यों इनमें से जो भी कम हो, की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

❑ **राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की किस धारा को संशोधित कर 'ग्राम सेवक' के स्थान पर 'ग्राम विकास अधिकारी' अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है-** [PSI (मो.या.)-12.2.2022][RAS-27.10.2021]
(1) 88 (2) 89 (3) 91 (4) 90
Ans. (2)

व्याख्या -राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, (संशोधन) विधेयक 2021 के बाद 'ग्राम सेवक' के पद नाम को बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया है।

❑ **राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरान्त ग्राम सेवक को जाना जाता है।** [II Grade (GK) 29.1.2023]
(1) कृषि पर्यवेक्षक के रूप में (2) ग्राम सचिव के रूप में
(3) ग्राम अधिकारी के रूप में
(4) ग्राम विकास अधिकारी के रूप में
Ans. (4) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❑ **ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है?** [PTI - 2015]
(1) पटवारी (2) सरपंच (3) उप-सरपंच (4) ग्राम सेवक
Ans. (4)

❑ **वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं?** [RAS-28.08.2016]
(1) 10 बार (2) 9 बार (3) 8 बार (4) 5 बार
Ans. (1)

व्याख्या-राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव आंध्रप्रदेश पंचायत राज पद्धति के आधार पर 1960 में हुआ। नवम्बर 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 11 बार (1960, 1965, 1978, 1981, 1988, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020) हो चुके हैं।

❑ **वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए -** [VDO-27.12.2021 (S-I)]
(1) 9 बार (2) 10 बार (3) 5 बार (4) 11 बार
Ans. (4) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❑ **वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है?** [LDC - 16.9.18]
(1) जिला परिषद (2) पंचायत समिति
(3) ग्राम पंचायत (4) कलेक्टर
Ans. (3)

Scanned with OKEN Scanner

> **व्याख्या** – *वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान ग्राम पंचायत को दिया जाता है।*

❑ राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2015 राजस्थान विधान सभा ने 27 मार्च, 2015 को पारित कर दिया। इसमें स्थानीय उम्मीद्वारों की पात्रता के लिए प्रावधान किया गया है- [RAS - 31.10.2015]

1. उनके घरों में शौचालय होना चाहिए। 2. जिला परिषद् की सदस्यता के लिए बी.ए. की डिग्री आवश्यक है। 3. पंचायत समिति की सदस्यता के लिए 10 वीं कक्षा पास होना आवश्यक है।4. सरपंच के लिए क्रमशः 8वीं कक्षा तथा अनुसूचित क्षेत्रों में उम्मीदवारों का 5वीं कक्षा पास होना आवश्यक है।

(1) 1, 3 और 4 सही हैं। (2) 2 और 4 सही हैं।
(3) 1 और 2 सही हैं। (4) 2, 3 और 4 सही हैं।

Ans. (1)

> **व्याख्या** –*राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2015 राजस्थान विधान सभा ने 27 मार्च, 2015 को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं शौचालय अनिवार्यता सम्बन्धी विधेयक पारित किया।*
>
> *राज्य सरकार ने 20 दिसम्बर, 2014 को अध्यादेश जारी कर पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन कर* ***सरपंच के चुनाव हेतु 8वीं पास*** *तथा* ***जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्य के लिए 10वीं पास*** *होना आवश्यक कर दिया है। अनुसूचित क्षेत्र के सरपंच हेतु 5वीं पास होना आवश्यक है। अतः* ***अब जिला प्रमुख, उपप्रमुख, प्रधान, उपप्रधान सभी का 10वीं पास होना जरूरी हो गया है।*** *राज्य सरकार ने 8 दिसम्बर, 2014 को अध्यादेश जारी कर पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया है कि चुनाव के प्रत्याशी के घर में शौचालय हो तथा उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं जाता हो।*
>
> - ***11 फरवरी, 2019 को पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए तय की गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को हटा दिया गया है।***

❑ **महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा दिया गया ?**

[II Grade (Science) Exam. 2011]

(1) 1992 का 70वाँ संशोधन (2)1992 का 73वाँ संशोधन
(3) 1992 का 74वाँ संशोधन (4) 1994 का 77वाँ संशोधन

Ans. (2)

> **व्याख्या** - *1992 के 73वाँ संविधान संशोधन द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में सभी निर्वाचित पदों पर (सदस्य व अध्यक्ष) सभी वर्गों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये।*

❑ **निम्न में से एक असत्य है।** [पटवारी प्रारम्भिक-2016]

(1) सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है।
(2) ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है।
(3) सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है।
(4) सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है।

Ans. (*)

> **व्याख्या :** *सरपंच के कर्तव्य - ग्राम सभा की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना। ग्राम पंचायत के अभिलेखों की रक्षा करना। ग्राम पंचायत के कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखना। समय-समय पर राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाना।*

❑ **राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है?**

[II Grade GK (संस्कृत शिक्षा) -19.02.2019]

(1) जिला कलेक्टर (2) जिला शिक्षा अधिकारी
(3) जिला प्रमुख (4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Ans. (3)

> **व्याख्या** –*राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख (जिला परिषद का अध्यक्ष) होता है।*

❑ **राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया?** [PTI (Grade-III)-25.9.2022]

(1) 23 अप्रैल, 1994 (2) 23 अप्रैल, 1995
(3) 24 अप्रैल, 1994 (4) 24 अप्रैल, 1995

Ans. (1)

> **व्याख्या** – *राजस्थान पंचायती राज अधिनियम- 1994 राजस्थान में 23 अप्रैल, 1994 से लागू किया गया है। इस अधिनियम के संदर्भ में 'राजस्थान पंचायती राज नियम 1996' बनाया गया है जो 30 दिसम्बर 1996 से लागू कर दिया गया है।*

Scanned with OKEN Scanner

❒ राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग, स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है?

[EO & RO : 14.05.2023 (S-II)]

(1) उदयपुर (2) जोधपुर (3) कोटा (4) जयपुर

Ans. (4)

❒ निम्न में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र स्थित नहीं है? [II Grade (Sans. Dept.) -12.2.2023(S-II)]

(1) मंडोर (2) अजमेर (3) सिरोही (4) डूँगरपुर

Ans. (3)

व्याख्या- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों को निम्नलिखित संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है: ☞ ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, मंडोर (जोधपुर) - 15.8.1960 से।

☞ पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, डूँगरपुर-3.2.1994 से।

☞ पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर-18.5.1996 से।

☞ हरिशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर व उदयपुर।

☞ इंदिरा गाँधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर

❒ इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के सम्बन्ध में कौनसा कथन सत्य है?

[पटवार परीक्षा - 2011]

(1) यह एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है।

(2) इसका उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं समस्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना है।

(3) इसका गठन पंचायती राज संस्थान तथा ग्रामीण विकास संस्थान का विलय कर किया गया है।

(4) समस्त वर्णित कथन।

Ans. (4)

व्याख्या- *इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से विभिन्न स्तरों पर जुड़े जन प्रतिनिधियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना है। इंदिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर (25 मार्च, 1989 को गठित) तथा राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का विलय का 'इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान' नाम दिया गया है।*

❒ पंचायत समिति के सदस्य : [पटवार परीक्षा - 2008]

[CET : 05.02.2023 (S-I)]

(1) मनोनीत होते हैं। (2) प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।

(3) अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं।

(4) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं।

Ans. (2)

व्याख्या- सदस्यों का निर्वाचन-

☞ *पंचायत समिति क्षेत्र से प्रत्यक्षतः निर्वाचित*

☞ *ग्राम पंचायत में प्रत्येक वार्ड में पंजीकृत वयस्क सदस्यों द्वारा प्रत्यक्षतः निर्वाचित*

❒ कौनसी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? [PSI (मोटर वाहन) - 12.02.2022]

(1) ब्लॉक समिति (2) ग्राम पंचायत

(3) जिला परिषद् (4) इनमें से कोई नहीं

Ans. (2) *व्याख्या : उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❒ महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है- [पटवार-23.10.2021 (Shift -I]

[RAS (Pre) Exam. 14 June, 2012]

[उद्योग प्रसार अधिकारी-22.08.2018][LDC-2012]

(1) जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (DRDA)

(2) राज्य सरकार (3) ग्राम पंचायत (4) ग्राम सभा

Ans. (3)

व्याख्या *- ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य : ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र में परिसरों का संख्यांकन, जनगणना, कृषि उपज उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम, ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विवरण, बेरोजगारी के आंकड़े, जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीयन और पंचायत अभिलेख इत्यादि ।*

❒ निम्न में से कौनसा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है- [CET : 05.02.2023 (S-II)]

(1) बिक्री कर (2) सम्पत्ति कर

(3) भूमि कर (4) आय कर

Ans. (3)

❒ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की किस धारा में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख किया गया है? [II Grade GK - 24.12.2022]

(1) 18 (2) 17 (3) 12 (4) 13

Ans. (4)

Scanned with OKEN Scanner

व्याख्या -राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की अध्याय एवं धाराएँ -

अध्याय - 1 : प्रारम्भिक

- धारा (1) : संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ
- धारा (2) : विभिन्न परिभाषाएँ

अध्याय - 2 : वार्ड सभा

- धारा (3): वार्ड सभा एवं उसकी बैठकें
- धारा (4) : वार्ड सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10या 10 प्रतिशत होगा।
- धारा (5) : वार्ड सभा की बैठक की अध्यक्षता संबंधित वार्ड पंच करेगा।
- धारा (6) : संकल्प
- धारा (7) : वार्ड सभा के कृत्य
- धारा (8): सतर्कता समिति

8 (क) ग्राम सभा और उसकी बैठकें

8 (ख) गणपूर्ति

8 (ग) पीठासीन अधिकारी

8 (घ) संकल्प

8 (ङ) ग्राम सभा के कृत्य

अध्याय - 3: पंचायती राज संस्थाएँ

- धारा (9): ग्राम पंचायत का गठन।
- धारा (10): पंचायत समिति का गठन
- धारा (11): जिला परिषद का गठन
- धारा (12) : पंचायत की संरचना
- धारा (13) : पंचायत समिति की संरचना
- धारा (14) : जिला परिषद की संरचना
- धारा (15) : सीटों पर आरक्षण (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं हेतु आरक्षण का प्रावधान)
- धारा (16) : सरपंच, प्रधान एवं जिला प्रमुख के पदों पर आरक्षण का प्रावधान।
- धारा (17) : पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल एवं चुनाव।
- धारा (18) : निर्वाचक एवं निर्वाचक नामावली
- धारा (19) : पंच या सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्यताएँ एवं आयु।
- धारा (19ए) : एक व्यक्ति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध।
- धारा (20) : एक ही समय किसी व्यक्ति के दो या अधिक पंचायती राज संस्थाओं की सदस्यता लेने पर प्रतिबंध
- धारा (45):पंचायत की बैठकें : प्रत्येक 15 दिन में कम से कम एक बैठक
- धारा (46) : पंचायत समिति की बैठकें : प्रत्येक माह में कम से कम 1 बैठक
- धारा (47) : जिला परिषद की बैठकें : प्रत्येक 3 माह में कम से कम 1 बैठक
- धारा (53) : किसी पंचायत को कृत्यों का समनुदेशन
- धारा (81) : विकास अधिकारी की शक्तियाँ और कृत्य
- धारा (82):मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारी
- धारा (83) : जिला परिषद का कर्मचारिवृन्द
- धारा (84) : मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों की शक्तियाँ और कृत्य
- धारा (85) : विकास अधिकारी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की आपात शक्तियाँ

अध्याय - 4 : राज्य सरकार आदि की शक्तियाँ

- धारा (92) : किसी पंचायती राज संस्था के संकल्प को रद्द या निलंबित करने की शक्ति
- धारा (94) : किसी पंचायती राज संस्थान को भंग करने की सरकार की शक्ति
- धारा (106) : नियमों और उप-विधियों का अतिलंघन
- धारा (107) : विवाद

अध्याय - 5 : प्रकीर्ण

- धारा (108) : सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे
- धारा (118) : वित्त आयोग का गठन
- धारा (119) : राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी और कर्मचारिवृन्द
- धारा (121) : जिला आयोजना समिति
- धारा (122) : वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट
- धारा (123) : कठिनाईयों का निराकरण
- धारा (124) : निरसन और व्यावृत्तियाँ

❐ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है?

[II Grade GK - 21.12.2022]

(1) 95 (2) 92 (3) 93 (4) 94

Ans. (4) **व्याख्या :** उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

❐. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है?[स्कूल व्याख्याता (शारीरिक शिक्षा)- 21.10.2022]

(1) 81 (2) 82 (3) 83 (4) 84

Ans. (4)**व्याख्या :** उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।

Scanned with OKEN Scanner

❑ **पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे?**[II Grp.-30.7.2023 (I)]

(1) 22 (2) 13 (3) 25 (4) 17

Ans. (4)

व्याख्या –पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख से अनधिक की जनसंख्या वाले किसी जिला परिषद् क्षेत्र में 17 निर्वाचन क्षेत्र होंगे और किसी ऐसे जिला परिषद् क्षेत्र के मामले में जिसकी जनसंख्या चार लाख से अधिक है, चार लाख से अधिक के प्रत्येक एक लाख या उसके भाग के लिए 17 की उक्त संख्या में 2 की बढ़ोतरी कर दी जायेगी।

❑ **ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है-**

[प्रवक्ता (तकनीकी शिक्षा विभाग) -12.03.2021]

(1) ग्राम सभा के सदस्यों के मतों का बहुमत।

(2) ग्राम सभा के सदस्यों के मतों का दो-तिहाई बहुमत।

(3) बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत।

(4) ग्राम सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत।

Ans. (3)

व्याख्या – *राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 8 (घ) के अनुसार 'ग्राम सभा को इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये विषयों से संबंधित कोई भी संकल्प ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना होगा।'*

❑ **राजस्थान में नगरपालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक है-** [कॉलेज व्याख्याता (सारंगी)30.05.2019]

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5

Ans. (4)

व्याख्या – *नगरपालिका चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गए उम्मीदवार के लिए एक एवं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए पाँच प्रस्तावक आवश्यक है।*

❑ **यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है, तो उसका निर्वाचन .....होना चाहिए।** [वनरक्षक-13.12.2022(S-II)] [IAS (Pre), 2009] [CET -11.2.2023 (S-I)]

(1) विघटन से तीन माह के अन्दर

(2) विघटन के छः माह के अन्दर

(3) विघटन से एक वर्ष के अन्दर

(4) कभी भी

Ans. (2)

व्याख्या – *प्रत्येक पंचायती राज संस्था का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक का होगा। जिला परिषद व पंचायत समिति में अध्यक्ष तथा पंचायत में उपसरपंच के निर्वाचन हेतु की गई बैठक प्रथम बैठक मानी जाएगी। इन संस्थाओं के चुनाव कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व तथा विघटन की स्थिति में विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर करवाने होंगे।* ***विघटन के पश्चात पुनर्गठित संस्था मूल संस्था की शेष अवधि के लिए कार्य करेगी।*** *पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व त्यागपत्र दे सकते हैं।*

❑ **कौनसा कथन असत्य है?** [III Grade (SST) -26.02.2023]

(1) पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव सम्पन्न कराने होंगे।

(2) शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत पाँच वर्ष के कार्यकाल तक रहती है।

(3) यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव करना आवश्यक नहीं है।

(4) पंचायत का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से पाँच वर्ष है।

Ans. (2) *व्याख्या – उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।*

❑ **निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के अनुसरण में-** (Patwar Main , 24.12.2016)

1. पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल, 1994 में लागू किया गया।

2. ग्राम सभा का वर्ष में दो बार आयोजन अनिवार्य है।

3. पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं का एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य है।

4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए भी एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य हैं।

उपर्युक्त कथन/कथनों में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए-

(1) 1 एवं 4 केवल (2) 3 एवं 4 केवल

(3) 1 एवं 2 केवल (4) 1, 2 एवं 3 केवल

Ans. (*) **उपर्युक्त चारों कथन सही है।**

Scanned with OKEN Scanner